



भारत का गज़त

The Gazette of India

अतिथारण
EXTRAORDINARY

भाग II—भाग 3—प्राप्त-प्राप्त (II)
PART II—Section 3—Sub-Section (II)

प्राप्तिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 621]

नई दिल्ली, मंगलवार, 22 सितम्बर 1992/माह 31, 1914

No. 621] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 22, 1992/BHADRA 31, 1914

इस भाग में भिन्न प्रकाशित संस्करण की जाती है जिसमें कि यह व्यक्ति संक्षेप के कानून में रखा जाता है।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विविध, व्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय

(विधायी विभाग)

प्रधिकारिता

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1992

का.धा 701 (अ) — राष्ट्रपति द्वारा किया गया नियमित आदेश
संविधान की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।—

आदेश

भी हृष्ट वर्ष मूलपूर्व संसद संविधान ने 12 फ्रांस्त, 1991 को एक आपने फाइल किया जिसने यह भ्रष्टिक्यन किया गया है कि लोक सभा के आसीन संविधान श्री पंकज और प्रीती भारत के संविधान के मनुष्ठेद 102 (1) (अ) के प्रधीन नियमित लड़ने के लिए अर्हित नहीं थे,

और भारत के राष्ट्रपति ने उक्त आपने के प्रतिनिर्देश से संविधान के मनुष्ठेद 103 (2) के प्रधीन नियमित आयोग की राय मांगी थी,

और नियमित आयोग की राय है (उपायव देखिए) कि भी हृष्ट वर्ष मूलपूर्व संसद संविधान के मनुष्ठेद 103 (1) के प्रधीन भारत के राष्ट्रपति की भ्रष्टिकरिता का प्रबलेवन नहीं लिया जा सकता है,

यह भव ने शक्ति द्वारा शर्मा भारत का राष्ट्रपति उत्तोत्त को व्याप में रखते हुए उक्त श्री हृष्ट वर्ष का ज्ञापन जारिं करता है।

14 सितम्बर 1992

भारत का राष्ट्रपति

उपायव

भारत नियमित आयोग के समक्ष

1991 का निर्देश मामला स 1

(भारत के संविधान के मनुष्ठेद 103 (2) के प्रवीन भारत के राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश)

निर्देश में लोक सभा के आसीन संविधान श्री पंकज और प्रीती की प्रविधित निरहृता।

राय

1 यह श्री हृष्ट वर्ष मूलपूर्व संसद संविधान द्वारा भारत के राष्ट्रपति को संबोधित तारीख 12 फ्रांस्त 1991 के ज्ञापन की प्रति "संमुचित कारंबाई के लिए" प्रवेषित करने वाला राष्ट्रपति संविधान से प्राप्त तारीख 16 फ्रांस्त 1991 का निर्योग है।

2. उक्त भाग में भी हर्ष वर्धन ने यह अधिकथन किया है कि भी पंकज चौधरी जो हाल में हुए साधारण निर्वाचन में उत्तर प्रदेश के महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से विद्यमान लोक सभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। 'भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (श) के अधीन निर्वाचन लड़ने के लिए अर्थात् नहीं है क्योंकि वह भारत के नागरिक नहीं हैं और वह नेपाल के नागरिक हैं।' अपने अधिकथन को सिद्ध करने के लिए उन्होंने अपने जापन के साथ नेपाल के कपिलवस्तु जिला के प्रशासनिक अधिकारियों के कुछ वस्तावज संलग्न किए हैं। उन्होंने राष्ट्रपति से शर्थना की है कि संविधान के अनुच्छेद 103 के अधीन अपनी अनित्यों का प्रयोग करते हुए वे "श्री पंकज चौधरी का निर्वाचित प्राप्तात्म कर दें और संविधान की भावना को बनाए रखने के लिए मन्य निर्देश दें जो वे ठीक समझें।"

3. उपरोक्त से यह प्रकट होता है कि श्री हर्ष वर्धन का अपना तर्क यह है कि श्री पंकज चौधरी भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (श) के अधीन निर्वाचित लड़ने के लिए अर्थात् नहीं थे या वे जो कहना चाहते हैं वह यह है कि श्री चौधरी उक्त अनुच्छेद के अधीन निर्वाचित सङ्केत के लिए निरहृत थे। उनके प्रकथन से यह स्पष्ट है कि यदि श्री पंकज चौधरी पूर्वोक्त निरहृता से प्रस्त थे भी तो वह उस समय ये जब उन्होंने लोकसभा का विद्यालय साधारण निर्वाचन लड़ा था। इस प्रकार वह निरहृता जिससे प्रस्त होने का अधिकथन किया गया है वह तारीख 19-6-91 को उनके निर्वाचन के दिन और उसके पूर्व विद्यमान थी। इसरे शब्दों में यदि यह मामला निरहृता का भी है तो वह निर्वाचन पूर्व निरहृता का है और यह ऐसी निरहृता का नहीं है जिससे वह जून 1991 में हुए पूर्वोक्त निर्वाचन के पावात् अधीन था या प्रस्त हो गए।

4. यह प्रक्षेप से परिनिर्धारित है कि संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अधीन राष्ट्रपति को निरहृता के केवल ऐसे मामलों में विनिश्चय करने की अधिकारिता है जिसमें संसद् का कोई भासीन सदस्य निर्वाचित के पश्चात् निरहृता से ग्रस्त हो जाता है। संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित भायोग को अधिकारित निरहृता के प्रश्न की जांच करने की भायोग की अधिकारिता भी उम्म दशा में उत्पन्न होती है जब मामला निर्वाचनोत्तर निरहृता का हो। निर्वाचित पूर्व निरहृता का प्रश्न शर्थात् वह निरहृता जिससे कोई अक्षित निर्वाचित के पूर्व किसी समय प्रस्त था लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के भाग 6 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 329(ख) के अधीन निर्वाचित अर्जी के भाष्यम से ही उड़ाया जा सकता है किसी भाष्य रीति में नहीं। इस संबंध में निर्वाचित भायोग बनाम शका वेंकट राव—1953 एस सी भार 1144 बुद्धावन नायक बनाम निर्वाचित भायोग—ए. आई. भार 1965 ए सी 1978 और निर्वाचित भायोग बनाम एन.जी. रंगा—ए. आई. भार 1978 एस सी 1609 वाले मामलों में उच्चतम ध्यायालय के निर्णयों के प्रति ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

5. विधि को उपरोक्त परिनिर्धारित प्रश्न को ध्यान में रखते हुए मेरी यह राय है कि संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अधीन भारत के राष्ट्रपति की अधिकारिता का अपलंब श्री पंकज चौधरी की अधिकथित निरहृता के संबंध में नहीं लिया जा सकता क्योंकि उनके (श्री हर्ष वर्धन) के प्रकथन के अनुभाव श्री पंकज चौधरी 19 जून, 1991 को अपने निर्वाचन के दिन और उसके पूर्व अधिकथित निरहृता से ग्रस्त थे। उन्होंने निर्वाचित भायोग को भी श्री पंकज चौधरी की अधिकथित निरहृता के उक्त प्रश्न की जांच करने की अधिकारिता नहीं है।

6. भायोग द्वारा राष्ट्रपति और कुछ राज्यों के राज्यपाल द्वारा कुछी संक्षय में भायोग को निर्दिष्ट किए गए मामलों में ऐसे ही विचार अधिकृत किए हैं। उदाहरण के लिए 1989 के निर्देश मामला से 6 में जो संविधान के अनुच्छेद 192(2) के अधीन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से जो निर्देश प्राप्त हुआ था उसमें यह प्रश्न उड़ाया गया था कि क्या श्री राजा मोहम्मद मोहम्मद खां एक निर्दिष्ट नागरिक था और उसे एक भारतीय नागरिक के रूप में विद्याने के लिए निर्वाचित नामावली में प्रविलिट की गई थी जिसके भायार पर उसने 1985 में उत्तर प्रदे-

षिधान सभा के लिए निर्वाचित लड़ा था। भायोग ने 1991 जून के राज्यपाल की अपनी राय में यही है कि संविधान के अनुच्छेद 192(1) के निर्वाचितों के अनुभाव उपरोक्त प्रश्न उसके ममक्ष उठाया नहीं जा सकता है क्योंकि यह निर्वाचित-पूर्व निरहृता से संबंधित था।

7. प्रस्तुत मामले को समाप्त करने से पूर्व मैं एक बार फिर संविधान के अनुच्छेद 103 (और राज्य विधान मंडल के सदस्यों से संबंधित अनुच्छेद 192 का तस्थानी उपर्योगी) और अनुच्छेद 329(ख) के उपर्योगी में अंतर की ओर ध्यान ध्याकरित करता आँखा। जैसा कि श्री भवताता विह और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के चार धन्य सदस्यों के अधिकथित निरहृता से संबंधित 1984 के निर्देश मामला से 2 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की भेजी गई भायोग की तारीख 29 अगस्त 1984 की रिपोर्ट में पहले ही कहा जा चुका है कि यदि कोई सदस्य अपने निर्वाचित समय निरहृता से ग्रस्त था और उसके सदन का सदस्य बन जाने के पश्चात् भी ऐसी निरहृता से वह ग्रस्त बना रहता है किन्तु यदि ऐसी निरहृता का मामला लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के उपर्योगों के अनुभाव निर्वाचित के पश्चात् नियत समय के भीतर निर्वाचित अर्जी के भाष्यम से उठाया नहीं गया है तो उस दशा में ऐसा कोई भव नहीं है जिसके ममक्ष संसद् या राज्य विधान मंडल के किसी भासीन सदस्य के अधिकथित निरहृता के प्रश्न को उठाया जा सके। भायोग ने अपनी उस राय में यह बताया था कि यह संसद् पर नियंत्र करता है कि क्या वह अपने सामूहिक विधिक से ऐसे समूचित उड़ाय करे जो वह इस कमी को दूर करने के लिए विधिक रूप से आवश्यक समझे। उस राय की एक प्रति भायोग ने तारीख 12-11-84 के अपने पत्र सं. 113/उ.प्र./3/84-एल.एस. आई. द्वारा विधि और ध्याय मंत्रालय में केंद्रीय सरकार को उपयुक्त कार्रवाई के लिए में यही है।

8. राष्ट्रपति संविधान से प्राप्त निर्देश को उपरोक्त भाष्य की मेरी राय के साथ बापस भेजा जा रहा है।

(टी.एन. शेषन)

भारत के मुख्य निर्वाचित भायोग

तारीख : 5 सितंबर 1991

[नं. 7/39/91-वि. -II]
पी.एल. सकरदाल, संयुक्त संविधि

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 1992

S.O. 701(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

ORDER

Whereas a memorandum, dated 12th August, 1991, has been filed by Shri Harsh Vardhan, Ex-M.P., alleging that Shri Pankaj Chaudhary, a sitting member of the House of the People, was not qualified to contest the election under article 102(1)(d) of the Constitution of India;

And whereas, the President of India had sought the opinion of the Election Commission under clause (2) of article 103 of the Constitution with reference to the said memorandum ;

And whereas, the Election Commission is of the opinion (vide Annex) that the jurisdiction of the President of India under article 103(1) of the Constitution cannot be invoked by Shri Harsh Vardhan;

Now, therefore, I, Shanker Dayal Sharma, President of India, do hereby dismiss the aforesaid memorandum of Shri Harsh Vardhan.

September, 14, 1992.

PRESIDENT OF INDIA

ANNEXURE

BEFORE THE ELECTION COMMISSION OF
INDIA

Reference case No. 1 of 1991

(Reference from the President of India under Article 103(2) of the Constitution of India)

In re · Alleged disqualification of Shri Pankaj Chaudhary, a sitting member of the House of the People.

OPINION

1. This is a Reference dated the 16th August, 1991 from the President's Secretariat forwarding "for appropriate action" a copy of the memorandum dated 12th August, 1991 addressed to the President of India by Shri Harsh Vardhan, Ex-Member of Parliament.

2. In the said memorandum, Shri Harsh Vardhan has alleged that Shri Pankaj Chaudhary who has been elected to the existing House of the People from Maharajganj Parliamentary Constituency in the State of Uttar Pradesh at the recently concluded general election "was not qualified to contest the election under Article 102(1)(d) of the Constitution of India, as he is not a citizen of India and is a citizen of Nepal". To substantiate his above allegation, he has annexed to his memorandum certain documents from some administrative authorities of the district of Kapilavastu in Nepal. He has prayed to the resident that in exercise of his powers under article 103 of the Constitution, he may "set aside the election of Shri Pankaj Chaudhary and give whatever other directions he may deem necessary to uphold the letter and spirit of the Constitution."

3. It will be observed from the above that Shri Harsh Vardhan's own case is that Shri Pankaj Chaudhary was not qualified to contest the election under Article 102(1)(d) of the Constitution of India or what he wants to say is that Shri Chaudhary was disqualified to contest the election under the said Article. It is apparent from his averment that Shri Pankaj Chaudhary was suffering, if at all, from the aforesaid disqualification even at the time when he contested the last general election to the House of the People. Thus, the disqualification from which he was alleged to have been suffering

subsisted prior to, and on the date of, his election on 19-6-91. In other words, it is a case of pre-election disqualification, if at all, and not of a disqualification which he incurred or to which he became subject after his aforesaid election in June, 1991.

4. It is well settled that under Article 103(1) of the Constitution, the President has the jurisdiction to decide only such questions of disqualification to which a sitting member of Parliament becomes subject after his election. The jurisdiction of the Commission to enquire into question of alleged disqualification on being referred to it by the President under Article 103(2) of the Constitution thus also arises only in cases of post-election disqualification. Any question of pre-election disqualification, that is, disqualification from which a person was suffering at the time of or prior to his election, can be raised only by means of an election petition under Article 329(b) of the Constitution read with Part VI of the Representation of the People Act, 1951 and in no other manner. Reference is invited in this connection to Supreme Court's decision in Election Commission vs. Saka Venkata Rao—1953 SCR 1144, Brundaban Naik vs. Election Commission—AIR 1965 SC 1892 and Election Commission vs. N.G. Ranga—AIR 1978 SC 1609.

5. Having regard to the above settled position of law, I am of the opinion that the jurisdiction of the President of India under Article 103(1) of the Constitution cannot be invoked by Shri Harsh Vardhan in relation to the alleged disqualification of Shri Pankaj Chaudhary as on his (Shri Harsh Vardhan's) own averments, Shri Pankaj Chaudhary was suffering from alleged disqualification at the time of, and prior to, his election to the Lok Sabha on 19th June, 1991. Accordingly, the Election Commission has also no jurisdiction to enquire into the above question of alleged disqualification of Shri Pankaj Chaudhary.

6. Similar view has been expressed by the Commission in a large number of cases referred to it by the President and Governors of certain States. For example, in reference case No. 6 of 1989 which was a reference received from the Governor of Uttar Pradesh under Article 192(2) of the Constitution, the question raised was whether Shri Raja Mohammad Amir Mohammad Khan was a British citizen and a bogus entry was made in the electoral roll to show him as an Indian citizen on the basis of which he contested election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly in 1985. The Commission conveyed its opinion to the Governor of Uttar Pradesh that the above question could not be raised before him in terms of Article 192(1) of the Constitution as it related to pre-election disqualification.

7. Before parting with the present case, I would once again like to invite the attention to the gap in the provisions of Article 103 (and corresponding provisions of Article 192 relating to members of State Legislatures) and Article 329(b) of the Constitution. As already pointed out in the Commission's Opinion dated 29th August, 1984 to the Governor of Uttar Pradesh in Reference Case No. 2 of 1984 regarding alleged disqualification of Shri Mandhata Singh and four other members of Uttar Pradesh Legislative Council, there is no forum before which the question of alleged disqualification of a sitting member of Parliament or State Legislature may be raised if the member was suffering from a disqualification at the time of his election and continues to suffer from such disqualification even after his becoming member of the House but the question of such disqualification is not raised by means of an election petition within the stipulated period after the election in accordance with the

provisions of the Representation of the People Act, 1951. The Commission also observed in that opinion that it was for Parliament, in its collective wisdom, to take appropriate measures as considered legally necessary to fill the lacuna. A copy of that opinion was forwarded for appropriate action to the Central Government in the Ministry of Law and Justice by the Commission by its letter No. 113/UP/3/84-LSI dated 12-11-84.

8. The Reference received from the President's Secretariat is returned with my opinion to the aforesaid effect.

T. N. SESHAN,
Chief Election Commissioner of India.

Dated 5th September, 1991.

[F. No. 7(39)91-Leg.II]
P. L. SAKARWAL, Jt. Secy.